POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2026/अंक 05

मासिक प्रेषण दि. 8 मई, पी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

# ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित



'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 मई, 2026 मूल्य 50 पैसे

## आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

कोरोना महामारी के बाद राजस्थान में देशी-विदेशी पर्यटकों को गांवों की कला संस्कृति, खेत-खलियान, प्राकृतिक सौंदर्य, खान-पान आदि लुभाने लगे हैं। उन्हें थ्री व फाइव स्टार होटलों से भी बढ़कर गांव की झोंपड़ी, चूल्हा, चक्की, एवं ग्रामीण महिलाओं के बनाए देशी व्यंजन जैसी चीजें पसंद आ रही हैं।

यह देखकर अच्छा लगता है कि विदेशी पर्यटक खेत से ताजा सब्जी तोड़ कर लाते हैं और चूल्हे पर खुद सब्जी बनाने का प्रशिक्षण लेते हैं। बाजरे-मक्के की रोटी हो या छाछ-राबड़ी जैसे कई आहार उन्हें ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। जयपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर जैसे कई जिलों के आस-पास के गांवों में यह नजारा देखा जा सकता है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पनप रही 'होम-स्टे' संस्कृति और जैविक फार्म हाउसों ने ईको-टूरिज्म के नए द्वार खोल दिए हैं।

यह ग्रामीण पर्यटन की अनदेखी विरासत को उभारने का समय है। इसके लिए गांवों में सड़कें, स्वच्छ पानी, बिजली, पर्यटक केंद्र और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ ही विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। साथ ही ग्रामीण समुदाय को प्रशिक्षित कर उन्हें सशक्त बनाना भी जरूरी है, ताकि वे पर्यटन का सीधे लाभ उठाकर स्वावलंबी बन सकें और गांव के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकें। इससे गांवों से पलायन रुकेगा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकेगी।

इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के विजन पर प्रदेश में लागू की गई 'राजस्थान होम स्टे योजना 2026' से जमीनीस्तर पर समुदाय आधारित पर्यटन, एमएसएमई एवं स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सकेगा।

## केंद्रीय सूचना आयोग ने 'नाता प्रथा' पर अपनाया सख्त रुख

केंद्रीय सूचना आयोग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश व गुजरात के कुछ हिस्सों में प्रचलित 'नाता प्रथा' पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को निर्देश दिया है कि इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सौंपी गई 'कार्रवाई रिपोर्ट' सार्वजनिक की जाए।

सूचना आयुक्त पीआर रमेश ने कहा है कि आरटीआई के तहत सभी सूचनाएं साझा नहीं की जा सकती, खास कर शिकायतकर्ता व उनके परिवारों से जुड़ी निजी जानकारी। लेकिन मंत्रालय द्वारा इस कुप्रथा पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (निजी जानकारियों व संवेदनशील हिस्सों को हटाकर) सार्वजनिक की जानी चाहिए। राजस्थान में बेची गई एक नाबालिक की सुनवाई के दौरान एनएचआरसी ने राजस्थान के एक गंभीर मामले का जिक्र किया, जिसमें एक नाबालिक लड़की को उसके पिता ने 'नाता प्रथा' के तहत ढाई लाख रुपए में बेच दिया। शुरुआती भुगतान के बाद शेष राशि नहीं मिलने पर पिता उसे वापस ले आया और दूसरी जगह पर 32 हजार रुपए में 'नाता' तय कर दिया। बाद में उत्पीडन से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली थी।

***विशेष कानून बने...***
*एनएचआसी ने इस कुप्रथा पर रोक के लिए विशेष कानून बनाने की सिफारिश की है। आयोग के अनुसार महिलाओं को ऐसे समझौतों के लिए मजबूर करने वालों पर मानव तस्करी की धाराओं में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जबकि नाबालिकों के मानलों में पॉक्सो कानून के तहत सख्त कार्यवाई जरूरी है।*

## पैसेंजर पायलट का बैग गुम, एयरलाइंस को देना होगा हर्जाना

विद्याधर निवासी अमन अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-तृतीय में अमेरिकन एयरलाइंस व एतिहाद एयरवेज कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार परिवादी अमन अग्रवाल अमेरिका से कामर्शियल पायलट का प्रशिक्षण लेकर भारत लौट रहे थे। 19 जुलाई 2023 को यात्रा करने के लिए टिकट बुक किया। जिसकी उड़ान ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूयार्क व आबूधापी होते हुए नई दिल्ली तक थी, लेकिन पहली फ्लाइट में देरी होने से उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई और उन्हें दूसरी फ्लाइट से भेजा। इस प्रक्रिया में उनका चेक-इन सामान सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ। नई दिल्ली पहुंचने के बाद उनके दोनों बैग नहीं मिले। बाद में एक बैग मिल गया, लेकिन दूसरा बैग नहीं मिला, जिसमें पायलट लाइसेंस, लॉगबुक, मेडिकल रिकॉर्ड व वीजा सहित कई महत्वपूर्ण कागज थे।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने पायलट का बैग गुम होने को अमेरिकन एयरलाइंस व एतिहाद एयरवेज कंपनी की गंभीर लापरवाही और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना। आयोग ने विपक्षी कंपनियों पर 11 हजार रुपए हर्जाना लगाया और साथ ही निर्देश दिया कि परिवादी अमन अग्रवाल के खोए सामान की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 1,30,572 रुपए ब्याज सहित दें।

## प्रदेश में नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें

प्रदेश के 1.75 करोड़ से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह राहत की खबर है कि इस वर्ष सभी श्रेणियों में बिजली की दरें यथावत रखी गई है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर फिक्स चार्ज समाप्त कर दिया गया है। अब इन कनेक्शनों पर 150 रुपए प्रति केवीए तक चार्ज नहीं लगेगा, जिससे चार्जिंग सस्ती होगी। मध्यम श्रेणी के उद्योगों को 30 पैसे यूनिट की राहत दी गई है। अब न्यूनतम विद्युत शुल्क 6.30 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। इससे उन्हें विभिन्न छूटों का अधिक लाभ मिलेगा।

## दहलीज से कारोबार तक फैले पंख

औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उद्यम स्थापना के लिए प्रदेश की करीब 3600 महिलाओं ने आवेदन किया है। इसमें जयपुर और चूरू जिले में 200 से अधिक महिलाएं हैं और 15 जिले ऐसे हैं, जिनमें आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या 100 से अधिक है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के मुताबिक कुछ समय से योजनाओं के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। जिससे स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्षेत्र में लगातार महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। योजना के तहत स्वरोजगार के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन दिलाया जाता है। बजट में 30 हजार युवाओं को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है।

## जल स्वावलंबन से बदली तस्वीर

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 से कम बारिश और गिरते भूजल स्तर से जूझ रहे प्रदेश के 5000 गांवों की तस्वीर बदली है। अभियान में वर्षा जल संचयन के लिए इन गांवों में एनीकट, चेक डैम, तालाब एवं जोहड़ बनाए गए हैं।

इससे पांच हजार गांवों के भूजल में सुधार हुआ है। कुओं व ट्यूबवेलों में जल स्तर बढ़ा है। गांवों में पेयजल व खेतों की सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ी है। बजट 2026-27 में इस अभियान के तीसरे चरण के तहत 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 5000 गांवों में 1,10,000 कार्य करवाने की घोषणा की गई है। किए जा रहे कार्यों से प्रदेश जल संकट से उबरकर एक आदर्श मॉडल के रूप में सामने आएगा।

## किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जी भूमिधारक बनकर जालसालों ने 440 करोड़ रुपए हड़प लिए। यह आंकड़ा प्रशासन की ओर से कराए गए सर्वे में सामने आया है। राज्य स्तर पर फर्जीवाड़ा उजागर होने पर राज्य व केंद्र सरकार ने छह लाख संदिग्ध किसान चिन्हित किए हैं और उनकी किस्त रोक दी है।

अब संदिग्ध खाताधारकों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए केंद्र सरकार एसओपी तैयार कर रही है। सरकार ने किसानों के लिए फार्मर आईडी कार्ड जारी किए हैं। यह कार्ड उन किसानों के लिए है, जिनके नाम जमीन है। फार्मर आईडी नहीं होने वालों को संदिग्ध माना गया है। इसके साथ जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के बाद दोबारा एक्टिव किया गया, उन सभी को भी संदिग्ध माना गया है।

## गांव जहां ग्रामीण बोलते हैं संस्कृत

राजस्थान के तीन गांव ऐसे हैं जिनमें 26 हजार ग्रामीण आपस में संस्कृत में बात करते हैं। यह भले ही चौंकाने वाली बात लगे, लेकिन इन तीनों गांवों में संस्कृत दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। यहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी संस्कृत में बातचीत करते हैं।

अजमेर जिले की 8 हजार की आबादी वाले सावर गांव के करीब 4,800, बूंदी जिले के कापरेन गांव के 14,000 और बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा गांव के सभी 7,000 ग्रामीण अब संस्कृत में ही बातचीत करते हैं। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हुआ। संस्कृत भारती नाम की संस्था 1996 से यहां लोगों को संस्कृत सिखा रही है। चित्तौड़ प्रांत के कार्यालय प्रमुख भूपेंद्र सिंह बताते हैं कि गनोड़ा में 100%, कापरेन में करीब 70% और सावर गांव में 60% लोग संस्कृत बोलते हैं।

## डूंगरपुर बना जल प्रबंधन की मिसाल

प्रदेश का डूंगरपुर जिला अब जल प्रबंधन की मिसाल बनकर उभर रहा है। यहां पिछले पांच सालों में 7 हजार 535 चेकडेम बनाए गए हैं। इन संरचनाओं से जिले में औसतन 6.5 मीटर तक भूजल स्तर बढ़ा है।

गांवों में जहां पहले गर्मियों में गंभीर जल संकट होता था, वहां अब जल स्त्रोत लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। इन गांवों में पानी की उपलब्धता पहले के मुकाबले दोगुनी हो गई है। जिले में जो कुएं और हैंडपंप पहले सूख जाते थे, वे अब लगातार पानी उपलब्ध कराते हैं। 15 साल से बंद पड़े कुंए फिर से उपयोग में आने लगे हैं। सिंचाई सुविधाएं मजबूत होने से इसका किसानों को भी बड़ा फायदा मिला है।

## खेती के लिए दिन में मिलेगी बिजली

प्रदेश के 22 जिलों के बाद अब दौसा व करौली जिले में भी किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली मिलने लगी है। अब प्रदेश के 24 जिलों के कृषि कनेक्शनों को दिन के दो ब्लॉक में बिजली सप्लाई हो रही है।

दौसा जिले में 33 केवी के 18 तथा करौली जिले में 33 केवी के 6 नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही दौसा में 33 केवी के 47 सब स्टेशनों पर ट्रांसफार्मरों में 128.95 एमवीए और करौली में 33 केवी के 15 सब स्टेशनों पर 49.45 एमवीए की क्षमता बढ़ाई गई है। दोनों जिलों में पीएम कुसुम योजना के 32 मेगावाट क्षमता के 17 सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित किए जा चुके हैं। जिनका फायदा किसानों को दिन में बिजली सप्लाई के रूप में मिलेगा।

## श्रमिक बेटियों के लिए 'शुभ शक्ति'

राजस्थान श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना के तहत निर्माण श्रमिक परिवार की अविवाहित बेटियों/महिलाओं को 55,000 रुपए की सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिक परिवार की बेटियों को शिक्षा और स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाना है।

स्वीकृत राशि का उपयोग शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार या विवाह में किया जा सकता है। इस योजना में पात्रता के लिए बेटियों की 18 वर्ष की आयु, 8वीं कक्षा पास और श्रमिक का एक वर्ष का पंजीकरण आवश्यक है। आवेदन ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों माध्यम से किए जा सकते हैं।

## प्रदेश में लगाए जाएंगे 10 करोड़ पौधे

राज्य सरकार इस बार भी मानसून के दौरान दस करोड़ पौधे लगाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को 'हरियालो राजस्थान' बनाया जाए। इसके लिए पांच साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई वन एवं पर्यावरण विभाग की बैठक में पौधारोपण लक्ष्य, चंदन वन, नमो वन एवं नमो नर्सरी की स्थापना के बारे में निर्णय लिए गए। पौधारोपण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है। पौधारोपण कार्य विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) से प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभियान के तहत किसानों को भी मुफ्त फलदार पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे।

## चुनावी मौसम और अनोखी परंपरा

तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित ओथावेडु गांव के लोगों का कहना है कि राजनीतिक शोर-शराबे के बिना भी स्वस्थ लोकतंत्र संभव है। उनका मानना है कि राजनीतिक प्रचार-प्रसार से मतदाताओं पर अनावश्यक प्रभाव पड़ता है।

राजनीतिक दल या उम्मीदवार गांव में आकर मौखिक रूप से वोट मांग सकते हैं। गांव में चुनावी मौसम में राजनीतिक पोस्टरों-बैनरों, झंडों और लिखित संदेशों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है। यदि कोई लगाता है, तो गांव के बुजुर्ग उसे तुरंत हटा देते हैं। ग्रामीण किसी भी प्रकार के प्रलोभनों, मुफ्त उपहारों, घोषणाओं के जाल में नहीं फंसते। गांव के लोग स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। चुनाव के दौरान गांव के लिए यह परंपरा एक मिसाल बन गई है। आसपास के कई गांवों में इसी तरह के नियम हैं।

## पारित नहीं हुआ महिला आरक्षण बिल

महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण का कानूनी कागजी हक 2023 में मिला, लेकिन इसे 2029 के आम चुनाव में लागू करने के लिए लाया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक फिलहाल लोकसभा में पारित नहीं हो पाया।

विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई यानी 352 वोट आवश्यक थे। लेकिन पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। अर्थात विधेयक को पारित करने के लिए 54 वोट कम पड़ गए। इससे फिलहाल महिला आरक्षण बिल फिर अटक गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि वह 2029 से महिला आरक्षण लागू करने के प्रयास जारी रखेंगे।

## जागरुक होंगे तेल व गैस उपभोक्ता

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.), भारत सरकार द्वारा तेल एवं गैस क्षेत्र में उपभोक्ता जागरुकता गतिविधियों के संचालन के लिए जयपुर स्थित वैश्विक सार्वजनिक नीति शोध एवं पैरवी संगठन कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी (कट्स) को सूचीबद्ध किया है।

इस के तहत 'कट्स' तेल व गैस उपभोओं को जागरुक करने के लिए विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाएं तथा उपभोक्ता संवाद आयोजित कर पी.एन.जी.आर.बी. के उपभोक्ता शिक्षा एवं सहभागिता को सुदृढ़ करने के प्रयासों में सहयोग करेगा।

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485